Implementation of Koodangulam Atomic power project

1964. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Govemment had discussed with the Russian delegation during their recent visit about the Russian aid to implement the Kood-ankulam Atomic Power Project;

(b) if so, what is the outcome of the discussions- and

(c) what are the steps contemplated to implement this project expeditiously?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (c) Owing to political developments in the erstwhile Soviet Union, discussions were initiated with the Russian Federation for reassessing the feasibility of setting up the 2xl000MW VVER Atomic Power Project at Kudankulam in Tamil Nadu. The Russian Federation, has indicated that the economic package as envisaged in the Inter-Governmental Agreement of 1988 would need to be modified. From the Indian side it has been emphasised that the project has to be economically viable both in respect of capital cost and unit energy cost. Both sides have agreed to continue discussions on the subject.

भारत का आणविक ऊर्जा कार्यक्रम

1965. श्री वीरेन जे० शाह :
श्री राम जेटमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 दिसम्बर, 1992 के "इकनामिक टाइम्स" में "इंडियन एन-एनर्जी प्रोग्राम अमंग वर्स्ट: वर्ल्ड वाच" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वाशिंगटन स्थित "वर्ल्ड वाच" संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट में भारत के आणविक कार्यक्रम की स्थिति शोचनीय बताई गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी : (क) तथा (ख) जी, हां। प्रश्न में उल्लिखित प्रैस रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि वर्ल्ड वाच संस्थान द्वारा "एमर्जिंग डेवलपमेंट: दि न्यू एनर्जी इन्वेशन" शीर्षक के अन्तर्गत किए गए अध्ययन जिसमें केवल परमाणु बिजली तक सीमित न रहकर बिजली के विकास और ऊर्जा को पूरा कार्य क्षेत्र शामिल है, में यह पाया गया है कि भारत और दूसरे विकासशील देश परमाणु बिजली के मामले में, अन्य औद्योगिक देशों की भांति अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाए हैं।

(ग) वर्ल्ड वाच संस्थान की रिपोर्ट सामान्य तौर पर सब देशों के और विशेष तौर पर सब विकासशील देशों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण है जो इस संबंध में काम कर रहे हैं। इकोनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि अधिक लागत और जटिल प्रौद्योगिकी की वजह से, परमाणु बिजली के अधिकांश विकासशील देशों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प सिद्ध होना मुश्किल है। जहां तक भारत का संबंध है, परमाणु बिजली कोयले की खानों के महानों से विशिष्ट दूरी से परे स्थित ताप बिजलीघरों से प्राप्त बिजली की तुलना में अधिक व्यवहार्य है। जहां तक प्रौद्योगिकी का संबंध है, भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है। जिन्होंने परमाणु ईंधन चक्र संबंधी पूरे क्रियाकलापों में क्षमता हासिल कर